



सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रामीण भारत का बहुआयामी विकास, संरचनात्मक चुनौतियाँ और परिवर्तन की संभावनाएँ

मनोज कुमार सिंह

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, जे. बी. महाजन डिग्री कालेज, चौरी चौरा, गोरखपुर, (उ०प्र०)

Article Info: (Received- 22/05/2026, Accept- 16/06/2026, Published- 10/07/2026)

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i7008

सारांश—

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDGs) इक्कीसवीं शताब्दी के वैश्विक विकास विमर्श की सबसे व्यापक एवं समावेशी अवधारणा के रूप में स्थापित हुए हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के अंतर्गत निर्धारित 17 लक्ष्य एवं 169 उपलक्ष्य ऐसे विकास मॉडल का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय तथा पर्यावरणीय संतुलन को परस्पर पूरक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत ने इन लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास रणनीति के साथ समन्वित करते हुए गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सम्मानजनक रोजगार, जलवायु कार्रवाई तथा संस्थागत सुदृढीकरण जैसे क्षेत्रों में अनेक नीतिगत एवं कार्यक्रमगत पहलें प्रारम्भ की हैं। इस व्यापक विकास प्रक्रिया में ग्रामीण भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की बड़ी जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण समाज ही है। पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG India Index के अनुसार अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, विद्युत उपलब्धता, वित्तीय समावेशन तथा संस्थागत सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं दूसरी ओर, बहुआयामी गरीबी, जलवायु परिवर्तन, कृषि आय की अनिश्चितता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुँच, लैंगिक विषमता, डिजिटल विभाजन तथा क्षेत्रीय विकास असंतुलन जैसी चुनौतियाँ अभी भी सतत विकास की गति को प्रभावित कर रही हैं।

कुंजी शब्द: सतत विकास लक्ष्य, ग्रामीण भारत, समावेशी विकास, बहुआयामी विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय शासन।

प्रस्तावना—

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विकास की अवधारणा केवल आर्थिक उत्पादन अथवा आय वृद्धि तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसका मूल्यांकन सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संरक्षण, मानवीय गरिमा तथा भावी पीढ़ियों के हितों के साथ किया जाने लगा है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को स्वीकार करते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की, जिनका मूल उद्देश्य "किसी को पीछे न छोड़ना" (Leave No One Behind) है। भारत ने

इन लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास नीतियों के साथ समेकित करते हुए उन्हें राज्यों तथा स्थानीय निकायों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। नीति आयोग को 'कले के समन्वय एवं निगरानी की केंद्रीय जिम्मेदारी प्रदान की गई है, जबकि राज्यों एवं जिला स्तर पर भी सतत विकास संकेतकों के आधार पर प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की वास्तविक सफलता ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सामाजिक समावेशन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि ग्रामीण भारत अब केवल कृषि उत्पादन का क्षेत्र न होकर राष्ट्रीय विकास, जलवायु अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार बन चुका है।

ग्रामीण भारत में विकास की प्रक्रिया बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, लैंगिक समानता, सम्मानजनक रोजगार, डिजिटल समावेशन, हरित ऊर्जा तथा स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ता एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इन लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानता, जलवायु परिवर्तन, भूमिहीनता, कृषि संकट, युवाओं का प्रवासन, लैंगिक विषमता, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुँच तथा संसाधनों के असंतुलित उपयोग जैसी समस्याएँ सतत विकास के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण भारत के विकास को केवल योजनाओं की संख्या या व्यय के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, संस्थागत क्षमता, सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरणीय संतुलन तथा जीवन की गुणवत्ता में आए वास्तविक सुधार के आधार पर समझना आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध-पत्र ग्रामीण भारत के बहुआयामी विकास, उसके समक्ष विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियों तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संभावनाओं का समग्र एवं आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शोध प्रविधि—

प्रस्तुत शोध पत्र गुणात्मक (Qualitative) तथा वर्णनात्मक—विश्लेषणात्मक (Descriptive-Analytical) शोध प्रविधि पर आधारित है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में ग्रामीण भारत के बहुआयामी विकास, संरचनात्मक चुनौतियों तथा परिवर्तन की संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किया गया है। अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), विश्व बैंक, नीति आयोग के SDG India Index, या National Indicator Framework, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारत की जनगणना 2011 तथा अन्य सरकारी प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। साथ ही समकालीन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रों, पुस्तकों, नीति-पत्रों तथा अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित शोध-अध्ययनों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध प्रमाणिक आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति, उपलब्धियों, सीमाओं तथा भविष्य की विकास-दिशा का वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है, जिससे नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा विकास योजनाकारों के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें।

सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा एवं ग्रामीण भारत में उनका महत्त्व—

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals—SDGs) ऐसी वैश्विक विकास अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों एवं अवसरों से समझौता किए बिना आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता तथा पर्यावरणीय संतुलन को एकीकृत रूप में स्थापित करने पर बल देती है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत 2030 सतत विकास एजेंडा के अंतर्गत 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य तथा 230 से अधिक वैश्विक संकेतकों का निर्धारण किया गया, जिनका उद्देश्य गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सम्मानजनक रोजगार, असमानताओं में कमी, जलवायु परिवर्तन का सामना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उत्तरदायी संस्थाओं का निर्माण सुनिश्चित करना है। भारत ने इन लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास नीति का अभिन्न अंग बनाते हुए नीति आयोग को इनके समन्वय एवं निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। SDG India Index राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन करता है, जिससे विकास की दिशा, उपलब्धियों एवं क्षेत्रीय विषमताओं का वैज्ञानिक आकलन संभव हो सका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 47 एवं 48।

में निहित सामाजिक न्याय, जनकल्याण, पोषण, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत भी सतत विकास की अवधारणा को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। ग्रामीण भारत के संदर्भ में इन लक्ष्यों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि, जल, वन, भूमि एवं जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, जल संकट, लैंगिक असमानता तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं किया जाता, तो राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भी अधूरी रह जाएगी। नीति आयोग के नवीनतम 'कळ सूचकांक' में भारत के समग्र प्रदर्शन में निरंतर सुधार परिलक्षित होता है, वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के माध्यम से खुले में शौच की समस्या में कमी लाने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा ग्रामीण आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने जैसी पहलों ने ग्रामीण विकास को सतत विकास लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण युवाओं का प्रवासन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, डिजिटल विभाजन तथा सामाजिक विषमताएँ यह संकेत देती हैं कि सतत विकास केवल योजनाओं के क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की सहभागिता, विकेंद्रीकृत शासन, वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समावेशी विकास रणनीति के प्रभावी समन्वय से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी कारण ग्रामीण भारत आज सतत विकास लक्ष्यों का मात्र लाभार्थी नहीं, बल्कि उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार एवं परिवर्तनकारी केंद्र बनकर उभर रहा है।

ग्रामीण भारत का बहुआयामी विकास—

ग्रामीण भारत का विकास वर्तमान समय में केवल कृषि उत्पादन अथवा आधारभूत संरचनाओं के विस्तार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तन की समेकित प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा इसी बहुआयामी दृष्टिकोण को स्वीकार करती है, जिसमें विकास का मूल्यांकन केवल सकल आय अथवा उत्पादन वृद्धि से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा मानवीय गरिमा के आधार पर किया जाता है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियाँ करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार बनी हुई हैं। इसलिए ग्रामीण विकास में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन तथा सामाजिक स्थिरता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पिछले एक दशक में ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दूरस्थ गाँवों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क से जोड़कर कृषि विपणन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आवासीय सुरक्षा एवं सामाजिक गरिमा में वृद्धि हुई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अगस्त 2019 में जहाँ केवल लगभग 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल से जलापूर्ति उपलब्ध थी, वहीं हाल के सरकारी आँकड़ों के अनुसार यह कवरेज 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत करोड़ों व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण तथा खुले में शौच मुक्त ग्रामों की घोषणा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा तथा स्वच्छता संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। ऊर्जा क्षेत्र में सौभाग्य योजना, एलपीजी कनेक्शन के विस्तार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है, जबकि डिजिटल इंडिया और भारतनेट परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स तथा ई-गवर्नेंस से जोड़ने की दिशा में नई संभावनाएँ विकसित की हैं। इसके समानांतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों ने मानव विकास के सूचकों में भी सुधार लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव तथा बैंकिंग सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच में सुधार के संकेत प्राप्त होते हैं, जबकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानता, सीमांत कृषि, भूमिहीनता, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, जलवायु परिवर्तन, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुँच तथा ग्रामीण युवाओं का बढ़ता प्रवासन यह स्पष्ट करता है कि बहुआयामी विकास की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रामीण भारत की भूमिका—

सतत विकास लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति में ग्रामीण भारत की भूमिका अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर निर्धारित अधिकांश लक्ष्य— जैसे गरीबी उन्मूलन (SDG-1), भूखमुक्त समाज (SDG-2), स्वास्थ्य (SDG-3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता (SDG-5), स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG-6), सम्मानजनक कार्य (SDG-8), असमानताओं में कमी (SDG-10), जलवायु कार्रवाई (SDG-13) तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (SDG-15) प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जीवन, कृषि अर्थव्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए यदि ग्रामीण समाज में सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं होता तो राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों की प्राप्ति भी अधूरी रह जाएगी। नीति आयोग द्वारा विकसित 'एक पदक पंक्ति' पदक पंक्ति राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करता है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, वित्तीय समावेशन तथा स्थानीय शासन में सुधार ने राष्ट्रीय प्रदर्शन को सुदृढ़ किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जो ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा तथा परिसंपत्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसी प्रकार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत करोड़ों महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म उद्यमिता एवं सामुदायिक नेतृत्व को सशक्त बना रही हैं। कृषि, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्थानीय खाद्य प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समाज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, ग्राम सभाओं की भागीदारी तथा स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन सतत विकास को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराता है। इस प्रकार ग्रामीण भारत केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप देने वाला सबसे महत्वपूर्ण विकास साझेदार है, जिसकी सक्रिय सहभागिता के बिना वर्ष 2030 तक निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना भी अधूरी रहेगी।

ग्रामीण विकास के प्रमुख आयाम—

ग्रामीण विकास की अवधारणा बहुआयामी है, जिसके अंतर्गत आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय, मानव विकास, पर्यावरणीय संरक्षण तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण परस्पर एक-दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास का प्रथम आयाम गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुरक्षा है, जिसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दूसरा आयाम कृषि एवं खाद्य सुरक्षा का है, जहाँ जलवायु-स्मार्ट कृषि, प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, किसान उत्पादक संगठन तथा मूल्य संवर्धन जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीसरा आयाम स्वास्थ्य एवं पोषण का है, जिसमें आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पोषण अभियान तथा आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास किया गया है। चौथा आयाम गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा का है, जहाँ समग्र शिक्षा अभियान, डिजिटल शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण मानव पूँजी के विकास का आधार बन रहे हैं। पाँचवाँ आयाम लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण तथा उद्यमिता कार्यक्रम ग्रामीण समाज में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ कर रहे हैं। छठा आयाम सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा आवास का है, जहाँ जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। सातवाँ आयाम पर्यावरणीय स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलन का है, जिसमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण तथा सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अंततः सुशासन एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण ग्रामीण विकास का ऐसा आयाम है, जो पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों तथा सामुदायिक आधारित संस्थाओं के माध्यम से विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इन सभी आयामों की पारस्परिकता यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण विकास किसी एक क्षेत्र की उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक सहभागिता के संतुलित समन्वय की सतत प्रक्रिया है। इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विकास की प्रत्येक नीति इन सभी आयामों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ संबोधित करे, जिससे ग्रामीण भारत में समावेशी, न्यायसंगत एवं दीर्घकालिक विकास की मजबूत आधारशिला स्थापित की जा सके।

संरचनात्मक चुनौतियाँ—

ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनकी जड़ें केवल आर्थिक संसाधनों की कमी में नहीं, बल्कि सामाजिक, संस्थागत, पर्यावरणीय तथा प्रशासनिक असमानताओं में भी निहित हैं। यद्यपि भारत ने विगत वर्षों में बहुआयामी गरीबी, ग्रामीण अवसंरचना, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विकास के लाभ सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं। भूमिहीनता, सीमांत जोतों की बढ़ती संख्या, कृषि आय की अनिश्चितता तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, मृदा क्षरण तथा भू-जल स्तर में गिरावट कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर जातिगत असमानता, लैंगिक भेदभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुँच तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों का सीमित सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण समावेशी विकास को बाधित करता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता तथा तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता डिजिटल विभाजन को बनाए हुए है, जिससे ई-शासन, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल वित्तीय सेवाओं एवं बाजार तक पहुँच में असंतुलन उत्पन्न होता है। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में निहित अनुच्छेद 38, 39, 46 एवं 48। सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं, किंतु इन उद्देश्यों की प्राप्ति राज्यों एवं क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हो सकी है। अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक समन्वय का अभाव, निगरानी प्रणाली की कमजोरी, स्थानीय निकायों की सीमित संस्थागत क्षमता तथा समुदाय की अपर्याप्त सहभागिता भी अपेक्षित परिणामों में बाधा पड़ रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं का निरंतर पलायन, कृषि में घटती लाभप्रदता, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित अवसर ग्रामीण विकास की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। स्पष्टतः सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति केवल योजनाओं की संख्या बढ़ाने से संभव नहीं होगी, बल्कि सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, स्थानीय संस्थाओं की क्षमता वृद्धि, वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा सहभागी विकास मॉडल को सुदृढ़ करने से ही इन संरचनात्मक चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है।

परिवर्तन की संभावनाएँ—

वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय विकास परिदृश्य में ग्रामीण भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभूतपूर्व परिवर्तनकारी संभावनाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत में तीव्र गति से विकसित हो रही डिजिटल अवसंरचना, ग्रामीण सड़क संपर्क, वित्तीय समावेशन, स्थानीय स्वशासन तथा सामुदायिक संगठनों का विस्तार विकास की नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। भारतनेट परियोजना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, जनधन, आधार, मोबाइल (JAM) त्रयी तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने ग्रामीण नागरिकों और राज्य के बीच पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासनिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, जल संरक्षण आधारित सिंचाई, ड्रोन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि परामर्श, किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा कृषि मूल्य श्रृंखला के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक उद्यमिता, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उद्यम ग्रामीण रोजगार के नए स्रोत विकसित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल भारत मिशन तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार से ग्रामीण युवाओं की उत्पादक क्षमता और नवाचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना निर्माण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित 'Leave No One Behind' की अवधारणा के अनुरूप यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, दिव्यांगजन तथा अन्य वंचित समुदाय विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी प्राप्त करें, तो ग्रामीण भारत सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास का वैश्विक उदाहरण बन सकता है।

सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का समालोचनात्मक विश्लेषण—

भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में समाहित करते हुए अनेक योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन किया है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत विकास को गति प्रदान करना है। नीति आयोग द्वारा तैयार 'कठ पदक' पदकमग राज्यों की प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगात्मक संघवाद को प्रोत्साहित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क

निर्माण तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल जीवन मिशन ने सुरक्षित पेयजल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने स्वच्छता व्यवहार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार तैयार किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी पहलें सतत विकास के विभिन्न लक्ष्यों को परस्पर जोड़ने का प्रयास करती हैं। इसके बावजूद इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन यह संकेत देता है कि योजनाओं के परिणाम राज्यों, जिलों तथा सामाजिक समूहों के बीच समान नहीं हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता की कमी, विभागीय समन्वय का अभाव, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, गुणवत्तापूर्ण निगरानी तंत्र की सीमाएँ, तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता तथा स्थानीय समुदाय की अपर्याप्त भागीदारी अपेक्षित उपलब्धियों को सीमित कर देती हैं। कई योजनाएँ अवसंरचना निर्माण तक तो सफल रही हैं, किंतु उनके दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर रही है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को अनेक विकास कार्यक्रमों में अभी भी समग्र रूप से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास योजनाओं में लैंगिक दृष्टिकोण, युवाओं की उत्पादक भागीदारी तथा स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है।

निष्कर्ष—

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत ने पिछले एक दशक में ग्रामीण विकास के विविध आयामों— गरीबी उन्मूलन, आधारभूत अवसंरचना, स्वच्छता, पेयजल, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा डिजिटल संपर्क में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। नीति आयोग के SDG India Index, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) तथा विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि अनेक सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक सुधार हुआ है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन, कृषि की अनिश्चितता, क्षेत्रीय असमानता, भूमिहीनता, सीमित औद्योगिक अवसर, डिजिटल विभाजन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तथा सामाजिक विषमताएँ आज भी सतत विकास के मार्ग में गंभीर अवरोध बनी हुई हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल योजनाओं का विस्तार अथवा वित्तीय निवेश ग्रामीण विकास का पर्याप्त संकेतक नहीं है; वास्तविक सफलता तभी संभव है जब विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुँचें और आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन तथा संस्थागत उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों तथा संयुक्त राष्ट्र के 'Leave No One Behind' के मूल दर्शन के अनुरूप ग्रामीण विकास को सहभागी, समावेशी तथा पर्यावरण-संवेदी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना समय की अनिवार्यता है।

सुझाव—

ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विकास नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं, सामाजिक विविधताओं तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिक लचीला एवं सहभागी बनाया जाए। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए स्थानीय स्तर पर मापनीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल खेती, प्राकृतिक कृषि, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, किसान उत्पादक संगठनों तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को व्यापक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि किसानों की आय एवं ग्रामीण रोजगार दोनों में स्थायी वृद्धि हो सके। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, कौशल विकास तथा स्थानीय मानव संसाधनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित समुदायों की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं तथा सामाजिक उद्यमिता को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर परिणाम-आधारित क्रियान्वयन, सामाजिक लेखा-परीक्षण तथा वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक वन प्रबंधन तथा हरित प्रौद्योगिकी आधारित निवेश को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाए। इन उपायों के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी, उत्तरदायी तथा सतत विकास की ऐसी संरचना विकसित की जा सकती है, जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा पर्यावरणीय संतुलन के मध्य दीर्घकालिक सामंजस्य स्थापित करते हुए भारत को वर्ष 2030

के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगी।

Author's Declaration

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Government of India. (1992). The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992. New Delhi: Government of India.
2. NITI Aayog. (2023). SDG India Index and Dashboard 2023–24. New Delhi: NITI Aayog.
3. United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
4. United Nations Development Programme. (2024). Human Development Report 2023/24. New York: UNDP.
5. World Bank. (2024). World Development Indicators. Washington, DC: World Bank.
6. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2024). National Indicator Framework for Sustainable Development Goals. New Delhi: MoSPI.
7. National Statistical Office. (2024). Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report 2023–24. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.
8. International Institute for Population Sciences, & Ministry of Health and Family Welfare. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21. Mumbai: IIPS.
9. Ministry of Rural Development. (2024). Annual Report 2023–24. New Delhi: Ministry of Rural Development.

Cite this Article-

'मनोज कुमार सिंह', "सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रामीण भारत का बहुआयामी विकास, संरचनात्मक चुनौतियाँ और परिवर्तन की संभावनाएँ", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:7, July 2026.

“Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author.”